समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 12 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

मोदी सरकार : बढ़ते कदम – डॉ. किशन कछवाहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पहले दिन से ही उत्साह जनक बना हुआ है। केन्द्रीय केबिनेट की पहली बैठक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों, छोटे कारोबारियों एवं व्यापारियों और कम आय वर्ग वाले अन्य श्रेणियों के लिये 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना' के तहत तीन हजार रूपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इस साल के अंत तक पांच करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी पांच वर्षों में 20 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले, रिक्शा व ठेला चलाकर अपनी आजीवका चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर, घरों में काम करने वाले जैसे 127 असंगठित क्षेत्रों के कामगारों, किसानों, लघु कारोबारियों–व्यापारियों को शामिल किया गया है। 60 साल की आयु पूरी हाने के बाद तीन हजार रूपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के 15 हजार रूपये तक की मासिक आमदनी वाले 18 से 40 आयु वर्ग के मजदूर इस योजना के हकदार होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सभी किसानों को सालाना 6000 रूपये मिलेंगे। इस योजना से सभी किसानों को लाभ मिलेगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा वादा किया भी था। इस योजना से देश के 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आतंकी और नक्सली हमले में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को दो हजार की जगह 2500 रू. प्रतिमाह मिलेंगे।

पांच साल बाद सरकार का जनाधार कम होने लगा है–इस विरोध के प्रचार को इस चुनाव में बड़ा धक्का लगा है। आधारहीन आरोपों और वादों के बावजूद जनता ने मोदी सरकार पर अटूट भरोसा जताया है। केबिनेट की पहली बैठक में ही प्रभावी निर्णयों से सिद्ध हो गया है कि वे सफलतापूर्वक देश को उपलब्धियों की मंजिल तक सरलतापूर्वक ले जा सकेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का न केवल व्यक्ति वरन् समाज और राष्ट्र के विकास के लिये अत्यंत महत्व है। इसका एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन जाना मोदी जी की दूरदर्शिता को दिखाता है।

मोदी जी की इस जीत में मुस्लिम महिलाओं का विश्वास जीतना भी एक बड़ा कारण बना। उन्हें लगा कि मोदीजी की नीतियाँ उनके और उनके परिवार के लिये अच्छी है। भाजपा ने मुस्लिम बहुल आबादी वाली 50 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं हैं।

एक बेहद साधारण परिवार में जन्में नरेन्द्र मोदी ने अनुशासित जीवन जीते हुये यह मुकाम हासिल किया है। यह प्रेरणा दायक ही है कि उनका बचपन कठिनाईयों और अभावों में बीता था। आज उनकी वही सरलता और सादगी वैसी ही देखी जा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के सांसदों की जीत के लिये जो अकूट मेहनत और प्रयास किय गये हैं, वे अत्यन्त प्रशंसनीय है। इससे चमत्कृत अमेरिकी पत्रिका 'टाईम्स' अपना स्वर बदलते हुये मोदीजी को 'भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला' बताने मजबूर हुयी है। चुनाव नतीजे आने के बाद 'सबका साथ सबका विकास – सबका विश्वास' सार्थकता के साथ स्वीकार्यता की और चार कदम आगे बढ़ा है।

कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिये प्रत्येक गरीब परिवार को रहने के लिये जमीन और 72000 प्रतिवर्ष देने का चुनावी वादा किया था–भारतीय राजनीति में किसी भी समूह को दिया गया यह एक बड़ा लालच था लेकिन देश का गरीब वर्ग इस लालच में नहीं फंसा। यह मोदी के जादू के सामने एक बड़ी अजीब और आश्चर्यजनक बात थी। कांग्रेस देश के 18 राज्यों में अपना खाता भी नहीं खोल पायी। नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कारण सन् 2019 के चुनावों में भारतीय लोकतंत्र को नये–नये आयाम मिले और नई ऊँचाइयाँ दी हैं।

मोदी ने राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के पराक्रम को सराहा है जिससे देश में एक नयी चेतना जागृत हुयी है। दूसरी ओर समाज के निचले वर्ग के लिये दी गयी कतिपय सुविधाओं के कारण उनमें आकाँक्षायें और अपेक्षायें भी बढ़ी हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके लिए मोदी कुछ भी करेंगे।

उत्तरप्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा–एनडीए गठबंधन ने 64 सीटें जीती हैं। इससे भी दूर–दूर तक यही संदेश गया है कि मतदाताओं को जातिवादी राजनीति के गणित के भरोसे बरगलाकर नहीं रखा जा सकता। अब नया मतदाता वोट देने से पहले देश, राज्य और समाज के बारे में सोचता है। उसका असल ध्यान इनके विकास पर भी है। अन्य विपक्षी दलों को मुस्लिम महिलाओं का अचानक मानस बदल जाना 'आश्चर्य में डालने वाला महसूस हो सकता है। इस समय उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की नीतियाँ, उससे भी ज्यादा 'मिशनमोड' वाले कार्यक्रम महिलाओं को आकर्षित करने वाले थे, शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, बैंक खाते और नये मकान का वादा इन वादों को व्यवहारिक रूप मिलते भी देखा जिसके कारण पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं ने अपने लिये सुविधाजनक समझा।

यद्यपि इस बीच मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिशें हुयीं लेकिन कांग्रेस नेताओं के मंदिर–मंदिर जाते देख बेअसर हुयीं। उन्होंने सेक्युलेरिटी की निकलती हवा को परख लिया था।

अब जहां तक सवाल है सरकार के सामने उपस्थित चुनौतियों का। यह सही है कि स्वयं मोदी जी ने 75 लक्ष्य तय किये हैं। जैसे किसानों की आय दुगुनी करना, 60 वर्ष की आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं को जो वर्षों से रूकी हुयी हैं को पूरा करना, प्रत्येक परिवार को पक्का मकान, सभी ग्रामीण परिवारों को एल.पी.जी गैस, सभी घरों की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, प्रत्येक घर तक शौचालय, सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, 115 मेगावाट बिजली उत्पादन, आयुष्मान भारत .के तहत, स्वास्थ्य केन्द्र, गरीब के दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधा आदि।

इन तमाम मामलों को गम्भीरता से लेते हुये मोदी जी की यह दूसरी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। केबिनेट की पहली मीटिंग में लिये निर्णय इस तथ्य के द्योतक हैं कि वे इन् मामलों में सजग है।

अमरीकी की दुखलंदाजी या मजबूरी – डॉ. किशन कछवाहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार में सामान्य तरजीही व्यवस्था (जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस–जी.एस.पी.) के तहत भारत को विकासशील देश के रूप में प्रशुल्क में छूट का लाभ समाप्त कर दिया है। इस अमेरिकी निर्णय से भारत के कुछ उत्पाद अमेरिका में मंहगे हो जायेंगे और सम्भव है प्रतिस्पर्द्धी बाजार में न टिक पायें। इस व्यवस्था को 5जून से लागू किया है। यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक मामलों के कई मुद्दे समय के साथ चलते रहते हैं और उन्हें बातचीत और परस्पर सहयोग से हलकर लिया जाता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों का बचाव करेगा। अमेरिका की सामान्य तरजीही व्यवस्था (जी.एस.पी.) चुनिन्दा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस की जनवरी में प्रकाशित रपट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था।

ट्रम्प सरकार की दलील है कि भारत कई क्षेत्रों में अपने बाजार तक अमेरिका को सामान और यथोचित पहुंच दिलाने में विफल रहा है। अमरीका कई मुल्कों को जी.एस.पी. की सुविधा देता है। इस प्रावधान के अंतर्गत अमरीका में कई भारतीय उत्पादों को बिना शुल्क आयात किये जाने की अनुमति है। यह सुविधा वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा जेम्स एवं ज्वेलरी जैसी वस्तुओं पर उपलब्ध है।

आज जबकि व्यापार में भारत की तुलना में अमरीका को चीन से 25 गुना घाटा हो रहा है, तब उस स्थिति में भी वह चीन से समझौतापूर्ण रवैया अपनाये हुये हैं। वहीं भारत के प्रति सख्ती का रवैया अपना रहा है। अमरीका को भारत के साथ व्यापार में मात्र 21.3 अरब डॉलर का ही घाटा सम्भावित है जबकि चीन के साथ व्यापार में यह घाटा 566 अरब डालर तक पहुंचता है। अमेरिका का यह रवैया भारत की दोस्ती के प्रति प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है।

अमेरिकी कम्पनियां अपने आर्थिक हित साधने के लिये हमेशा सक्रिय और प्रयत्नशील रहती है। कुछ समय पहले भी पेटेंट कानून में बदलाव लाने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की गयी थी।

अमरीका भारत से सूचना प्रोद्यौगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि गतवर्ष फरवरी माह में ही भारत ने उत्पादों पर आयात शुल्क 10 से 20 प्रतिशत कर दिया था। अमरीका की मांग स्वीकार कर लेने से अमरीका को तो कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, इसके विपरीत चीन के मोबाईल फोन पहले से अधिक मात्रा में भारतीय बाजारों में आने लगेंगे। भारतीय नेतृत्व को इस मामले में सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है।

अमेरिका को इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने की आवश्कता है कि भारत अमेरिका के आर्थिक और युद्ध क्षेत्र विषयक सामरिक हितों के लिये एक बड़ा उपयोगी देश है। यदि भारत की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि होती है यह भी अमरीका के लिये अत्यंत उपयोगी है।

क्या इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया जाना चाहिये कि अमरीका द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम तेल और गैस निर्यात किया जाता है जिसकी कीमत 4.5 अरब डालर है, और अभी इसके बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ भारत को आगामी सात वर्षों में 300 वोईंग विमान भी बेचना है जिसकी लागत 39 अरब डालर के आसपास हो सकती है। इसके अलावा और भी अनेक रक्षा सौदे हो रहे हैं और होने की सम्भावना है। उक्त संदर्भित घाटा आने वाले वर्षों में नफा में भी बदल सकता है।

अगर मत विभिन्नतायें ऐसे ही बढ़ती रहीं, और मनोवैज्ञानिक दबाव का सहारा लिया जाता रहा तो भारत को भी अपनी चुप्पी तोड़ने बाध्य होना पड़ सकता है। अमेरिका को यह बात सममनी होगी कि वह भारत के साथ सहयोगात्मक रूख अपनाकर ही अपने व्यापारिक हितों को साध सकता है क्योंकि नये भारत के लिये रोजगार का संरक्षण एवं संवर्धन, जनस्वस्थ्य की रक्षा और अपने उद्योगों की रक्षा करना भी अत्यन्त आवश्यक कार्य है।

गत कुछ महिनों के दौरान ट्रंप सरकार द्वारा कतिपय ऐसे कदम उठाये गये हैं जिनके कारण भारत पर नकारात्मक असर पड़ने की सम्भावनायें बढ़ रही है। पहले अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाया। यह एक ऐसा समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी थीं। भारत के लिये यह बड़ी समस्या है क्योंकि उसे तेल की कीमतें नीचे लाना एक चुनौती से कम नहीं हैं, अब उसने पूर्व में उल्लिखित तरजीही व्यवस्था समाप्त कर दी। यह भी अमरीका की मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि वह इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से आपसी सम्बन्ध प्रगाढ़ हुये हैं। अमरीका राष्ट्रपति ने इन सम्बंधों का अनेक अवसरों पर उल्लेख भी किया है। भारत एक बड़ा बाजार है। जी.एस.पी. खत्म होने से भारतीय उत्पाद अमरीकी बाजार में कड़ी स्पर्धा झेलने मजबूर होंगे। हालांकि इस फैसले का असर कई देशों पर पड़ेगा। भारत में ज्यादा चिन्ता जतायी जा रही है क्योंकि भारत स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की चुनौतियों से मुकाबला कर रहा है। उसमें एक चुनौती नियति दर बढ़ [illegible] है।

ऐसा भी हुआ है भारत देश में

भारत में कई राजनेताओं को जानता हूँ किंतु अधिकांश में दिमाग नहीं पाया। मेरा एक मित्र भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ था। उनका नाम था जनरल चौधरी। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो इस आदमी ने प्रधानमंत्री से हमले का मुकाबला करने की अनुमति मांगी। सरल सैन्य रणनीति है कि बचाव का सबसे अच्छा तरीका आक्रामक होना है। चौधरी का सुझाव था कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर हमला किया है, तो हमें पाकिस्तान पर चार–पांच मोर्चों पर आक्रमण करना चाहिए। वे समझ नही पाएंगे कि अपनी सेना कहां भेजें? लेकिन उफ्फ ये राजनेता!

प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें कहा कि सुबह 6बजें तक इंतजार करो। जनरल चौधरी ने मुझे बताया कि उसके बाद उन्हें सेना से निकाल दिया गया था, लेकिन यह बात सार्वजनिक नहीं की गई। सार्वजनिक रूप से तो वे ससम्मान सेवानिवृत्त हुए। मगर उनसे कहा गया था कि या तो इस्तीफा दें या आपको बाहर निकाल देंगे। अपराध क्या था उनका? अपराध था कि उन्होंने छह बजे के स्थान पर सुवह 5 बजे पाकिस्तान पर हमला कर दिया क्योंकि उनकी नजर में यही सही समय था। सुबह पांच बजे का समय एकदम उपयुक्त था– सब लोग सो रहे थे, वे लोग हक्के– बक्के रह गए और उसने जैसा कहा था, वैसा ही हुआ–उसने पूरे पाकिस्तान को थरथरा दिया। देखते ही देखते भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर से सिर्फ 15मील दूर रह गई। तब तक राजनेता क्या कर रहे थे? पूरी रात नेहरू और उनकी कैबिनेट विचार–विमर्श में उलझी रही–ऐसा करने का क्या नतीजा होगा, वैसा करने से क्या होगा और सुबह 6 बजे तक भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तभी उन्होंने रेडियो पर सुना–जनरल चौधरी लाहौर में प्रवेश कर रहे हैं।

यह स्थिति राजनेताओं के लिए असहनीय थी। उन्होंने लाहौर से सिर्फ 15 मील दूर उन्हें रोक दिया और जहां तक मैं समझता हूँ, यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी। उस दिना लाहौर जीत लिया जाता तो कश्मीर की समस्या और भारत का सिरदर्द हमेशा के लिए हल हो गया होता। कश्मीर के उस क्षेत्र की समस्या अब कभी हल नहीं हो सकती, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है–और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जनरल चौधरी को वापस आने के लिए कहा गया। कहा गया कि भारत एक अहिंसक देश है और आपने आदेश का इंतजार नहीं किया।

– ओशो

ये कैसे पत्रकार

नई दिल्ली। मजहब देखकर कलम चलाने वाली सेकुलर पत्रकारिता ने दिल्ली के मोती नगर इलाके में गत 16 मई 2019 को हुई ध्रुव त्यागी की हत्या पर चुप्पी ओढ़ली थी क्योंकि हत्यारे उन्मादी मजहबी थे। ध्रुव को इसलिये मारा गया था क्योंकि वह अपनी बेटी पर अश्लील छींटाकशी करने वाले अपराधी तत्वों का विरोध करने गया था। यदि अखलाक की मौत पर विशेष रिपोर्ट छपे लेकिन डॉ. नारंग से ध्रुव त्यागी तक की मौत पर एक शब्द न निकले, तो वह पत्रकार नहीं, पक्षकार है।

मीडिया की विश्वसनीयता : एक चुनौती

गत सप्ताह विश्व संवाद समिति, जालंधर के तत्वावधान में नारद जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्या धाम, श्री गुरू गोविन्द सिंह एवेन्यू में 'फेक न्यूज, फेक नैरेटिव के दौर में लोकतंत्र प्रहरी मीडिया की साख' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एकवांस्ड स्टडीज, शिमला के निदेशक प्रो. मकरंद परांजपे एवं अध्यक्षता सेवानिवृत्त सहायक केन्द्र निदेशक–दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर सरदार श्री मनोहर सिंह भारज ने की।

इस मौके पर श्री मकरंद परांजपे ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता पर लोगों का भरोसा वर्तमान समय में भी स्थायी है। परंतु इस भरोसे को बनाए रखने की चुनौती मीडिया पर ही है। मीडिया को विश्वसनीयता बचाए रखने का फर्ज स्वयं निभाना है। मीडिया जो उद्देश्य लेकर चला था, वह कहीं–कहीं अपने पथ को छोड़ अपनी भूमिका बदल रहा है। कई पत्रकार या मीडिया संस्थान आज स्वार्थ के आधार पर एक छिपा हुआ नैरेटिव प्रसारित करते हैं, जिसमें सत्य की मात्रा अपने हिसाब से तय की जाती है। लेकिन अन्ततोगत्वा जीत सत्य की ही होती है। इसीलिए फेक न्यूज या धारणाएं कभी जीत नहीं सकतीं। उन्होंने कहा कि मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तीव्रता पर हमला आज कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही कुछ मीडिया संस्थानों को बैन कर दिया गया था। मीडिया तब भी नहीं झुका था, आज भी नहीं झुकेगा, बस वह अपने उद्देश्य व सिद्धान्तों से भटके नहीं। कार्यक्रम के अध्यक्ष सरदार श्री मनोहर सिंह भारज ने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। मीडिया अपना कार्य निरपेक्ष भाव से करे, इसके लिए मीडिया के साथ लोगों का संवाद जरूरी है।

मीडिया का एक वर्ग रवैया बदलने तैयार नहीं

गुरूग्राम में एक मुसलमान युवक का सिर्फ यह कह देना रातों–रात राष्ट्रीय का चर्चा का विषय बन जाता है कि उसे कुछ लोगों ने पीटा और भारतमाता की जय बोलने कहा। लेकिन झूठी बात का भंडाफोड़ हो गया सी.सी.टी.वी. वीडियो सामने आ जाने पर। लेकिन सच्चाई सामने आ जाने के बावजूद, पुलिस द्वारा पत्रकारों को बुलाकर सारे तथ्य बता दिये जाने के बाद भी सभी चैनलों और अखबारों ने उस झूठी खबर को जारी रखा।

"स्वजनों की मदद से आगे आए समाज"

हाल ही में ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान(फेनी)ने तटीय क्षेत्रों समेत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। घर, दुकान, मकान सब तबाह हो गए। हालत यह है कि पीने के पानी तक का संकट है। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उसके समविचारी संगठन युद्ध स्तर पर सेवा कार्यों में लगकर स्वजनों का दुख दूर रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने पिछले दिनों तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा को नजदीक से जाना। श्री आलोक कुमार ने हालात का जायजा लेने के बाद बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता राहत कार्यों में लगे हुए हैं। इस दौरान वे भोजन से लेकर, वस्त्र, तिरपाल, सोलर लालटेन, पशु आहार तक उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का नुकसान हुआ है, ऐसे में विश्व हिन्दू परिषद् पूरे समाज से अपील करता है कि वह प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उदारता से दान करें। हमें विश्वास है कि समाज इस काम के लिए पर्याप्त मदद करेगा और हम संकट की घड़ी में ओडिशा की जनता की प्रभावी सहायता कर सकेंगे।

बंगाल की राजनीति पर हावी जिहादी

स्वतंत्रता के पश्चात बंगाल में इतनी हिन्दू विरोधी सरकार कोई नहीं आयी। ममता राज में दुर्गापुर के खादगढ़ा में बम–विस्फोट हुआ था जिसमें टीएमसी के एक सांसद शामिल थे। कलियाचक में जिहादियों ने पहले तो पुलिस स्टेशन को लूट लिया और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। पिछलें साल इस्लामपुर के एक स्कूल में जबरदस्ती उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। इस विवाद को लेकर हुए आन्दोलन में 2 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक महिला का चलती कार में बलात्कार हुआ और दोषियों को 10–10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं एक महिला हैं, ने बयान दिया कि लड़की का ही चाल–चलन ठीक नहीं था। इन कारणों से हिन्दुओं के मन में ममता के लिए घृणा का भाव पैदा हुआ और जब ममता को यह मालूम चल गया कि इन चुनावों में लोग भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट उनके गुप्तचर विभाग द्वारा दी गयी है, तो इन हालात में वे एकदम बौखलाई गई हैं। ममता को पता चल गया है कि नरेन्द्र मोदी के नाम पर हिन्दू व मुस्लिम समुदाय एक हो रहे हैं।

बेशक, जिहादी ताकतों का बंगाल की राजनीति पर दबदबा है। 2007 में कोलकाता में हिंसा हुई, लेकिन उसमें तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उपद्रव करने वाले आरोपी को ममता ने अपनी सरकार में कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया हुआ है। वह पिछले 30 वर्षों से जमात का सचिव रहा है। उन्होंनें ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है, जो खुलेआम कोलकाता कोक 'मिनी पाकिस्तान' बोलते हैं।

अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

नरेन्द्र मोदी का जादू गुजरात में साफ दिखाई दिया। भाजपा ने क्लीन स्वीप किया. यहां 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। राजस्थान में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। यहां भाजपा को 25 सीटें मिलीं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 4 सीटें जीतीं यहां भी कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई। उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भाजपा का कब्जा। कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट। अरूणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को जीरो मिला। यहां भाजपा ने दो सीट जीती। दिल्ली की सभी सात सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। लेफ्ट के किले को दरका कर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भी कब्जा किया। दमन दीव की एकलौती सीट को भाजपा ने अपने नाम किया। मणिपुर में पहली बार कमल खिला है। यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यहां एनपीएफ और बीजेपी ने एक–एक सीट हासिल की। मिजोरम की एक मात्र सीट को कभी कांग्रेस के पास थी उसे भाजपा के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत लिया। यहां से लाल रोसंगा ने जीत दर्ज की।

सर्वजातीय सामूहिक विवाह : एक प्रेरक उदाहरण

पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर में समाज की भिन्न–भिन्न 11 बिरादरियों के 41 युगलों का सामूहिक विवाह संस्कार एक ही पंडाल में पूज्य संतवृन्दों के आशीष व सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। विवाहोपरान्त पूज्य संत श्री अकिंचन महाराज, संत श्री मुन्नादास जी, संत श्री हरिशंकरदास एवं संत श्री मनीषदास जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। नव दम्पत्ति में पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित हो, इस हेतु प्रत्येक वर एवं वधू को तुलसी पौधे प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि 10 वर्ष पूर्व समाज में सेवा, समरसता व अनावश्यक व्यय से बचने के उद्देश्य से राजस्थान के सेवा भारती द्वारा सर्वजातीय विवाह के आयोजनों का शुभारम्भ भवानी मण्डी से किया गया था। इसी क्रम में अब तक पूरे राजस्थान के 13 जिलों के 25 स्थानों के 1897 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं।

इस पहल से लोगों को खर्चीले वैवाहिक आयोजन से राहत मिली है। बहुत ही सामान्य यपंजीयन शुल्क लेकर विदाई के पश्चात गृहस्थी के लिए आवश्यक

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

अब कहाँ गए वे मानवाधिकारी?

मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किसी भी समाज के माथे पर कलंक है। यह एक घिनौना अपराध है जिसे किसी जाति समुदाय या मजहब विशेष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन कठुआ मामले को पूरी तरह सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। बच्ची का नाम जान–बूझकर सार्वजनिक किया गया क्योंकि रसाना गांव के एक सम्मानित हिन्दू परिवार पर 'सामूहिक बलात्कार' का आरोप लगाया गया था। आनन–फानन में देश भर में वामपंथी, सेकुलर बुद्धिजीवी सक्रिय हो गए। जम्मू–कश्मीर और दिल्ली में प्रदर्शन हुए। यही नहीं, करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और हुमा कुरैशी जैसी जानी–मानी अभिनेत्रियों ने 'मैं शर्मिंदा हूँ', 'हमारी बच्ची के लिए न्याय', 'आठ वर्षीय के साथ देवी मंदिर में गैंग रेप, हत्या' की तख्तियां लेकर तस्वीरें खिंचवाई जो तेजी से सेकुलर मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो गईं। यह एक सोची–समझी रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत हिंदू धर्म, हिंदुओं और मंदिरों को बदनाम किया जाना ही एकमात्र उद्देश्य था।

मामले ने पूरा राज्य में ऐसा तूल पकड़ा कि इसकी सच्चाई जानने वाले आरोपियों के पक्ष में लामबंद हो गए। राज्य के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले को सुनियोजित तरीके से मीडिया, बुद्धिजीवियों तक ले जाने वाले तालिब हुसैन को उसी की बकरवाल बिरादरी के स्थानीय नेताओं ने बेनकाब किया कि उसे कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का संरक्षण प्राप्त है और कैसे भारी रकम का लेन–देन हुआ और कैसे पीड़िता बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद के नाम पर दिये गए चंदे की रकम को हुसैन ने अपने लिए इस्तेमाल किया। सुर्खियां बटोरने के बाद हुसैन खुद भी जेल गया। उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया, तो उसी साली ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया। एक मासूम बच्ची के नाम पर राजनीति करने वालों की अपनी खुद की क्या फिरत है, यह बहुत जल्दी जनता के सामने आ गया।

एक ही राज्य के दो दिल दहला देने वाले मामले। लेकिन दोनों पर बुद्धिजीवियों, सेकुलरों की प्रतिक्रिया का तरीका एकदम अलग। शायद इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों ही मुसलमान हैं। इस मामले को उठाने में उन्हें कोई सामाजिक, राजनीतिक या मजहबी फायदा नजर नहीं आता। यदि आरोपी का नाम ताहित अहमद मीर न होता, कोई हिंदू नाम होता तो इनकी दुकानदारी जम जाती। दरअसल, ऐसे लोग किसी मामले को उसकी गंभीरता को देखते हुए नहीं उठाते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि उसको उठाने से उन्हें कितना लाभ हो सकता है। इनसे जुड़े महिला संगठन भी इसी तर्ज पर काम करते हैं। ये देखते हैं कि जिस राज्य में घटना हुई, वहां सरकार किसकी है? यदि कांग्रेसी, समाजवादी या वामपंथी सरकार होती है तो ये चुपी रहते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो यह साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, उन्मादी है और मानवाधिकारों का हनन करती है और भाजपा के राज में कानून–व्यवस्था खराब है। इन सेकुलरों का जबरदस्त नेटवर्क है। सेकुलर मीडिया, कलाकार, बॉलीवुड, लेखक, शैक्षिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सब एक इशारे पर लामबंद लोकर एक स्वर में आवाज बुलंद करते हैं।

एक आठ वर्ष की बच्ची, एक तीन वर्ष की बच्ची, दोनों, मुस्लिम। एक ही मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं, दूसरी की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो गई है। तीन वर्षीया पीड़ित बच्ची जिंदा है और उस दरिंदे को पहचानती है जिसने उसके साथ पाश्विकता की। लेकिन चारों ओर खामोशी है। न अब कोई शर्मिंदा है, न अब कोई मजहबी रंग दिया जा रहा है। कोई कैंडिल मार्च नहीं हुआ। कठुआ मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने वाली जानी–मानी वकील इंदिरा जय सिंह ने तो मानो जुबान पर ताला ही लगा लिया है। स्वरा भास्कर को उस बच्ची से ज्यादा चुनाव में दिलचस्पी रहीं। करीना कपूर खान और शबाना आजमी ने एक बार भी नहीं कहा कि रमजान के पाक महीने में छोटी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी इस्लाम पर कलंक है।

आखिर यह एकतरफा सोच क्यों? दरअसल, वाम विचारधारा से जुड़े लोग किसी घटना पर कुछ बोलने से पहले पीड़ित का मजहब या जाति देखते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है।

पृष्ठ क्रमांक 3 का शेष भाग

सभी सामग्री समाज के सहयोग से नवदम्पत्ति को भेंट की जाती है। उन्हें सामाजिक न्याय विभाग का प्रमाणपत्र भी दिलाया जाता है। समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति में सम्मानपूर्वक वैवाहिक अनुष्ठान पूर्ण होकर उनके जीवन की मधुर स्मृति बनता है। इस वर्ष अभी तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 100 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं।

अंततः समाज को बांटने वाली शक्तियों की हार हुयी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने लोकसभा चुनाव के निर्णय के बाद कहा कि यह चुनाव भारत की दो भिन्न अवधारणाओं के बीच था। एक तरफ भारत की प्राचीन अध्यात्म आधारित एकात्म(Integral), सर्वांगीण और सर्वसमावेशी जीवनदृष्टि या चिंतन था। जिसे दुनिया में हिन्दू जीवन दृष्टि या हिन्दू चिंतन के नाम से जाना जाता रहा है। दूसरी ओर वह अभारतीय दृष्टि थी जो भारत को अनेक सस्मिताओं में बांट कर देखती रही है। और अपने निहित स्वार्थ के लिए समाज को जाति, भाषा, प्रदेश या उपासना पंथ के नाम पर बांटने का काम करती रही है। इस पृथक करने और बांटने की राजनीति करने वालों ने हमेशा समाज को जोड़ने वाली, एकात्म दृष्टि से देखने वाली शक्ति का विरोध ही किया है। और इस के बारे में तरह–तरह के आधारहीन झूठे आरोप लगाकर गलतफहमी निर्माण करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के साथ ही चल रही यह वैचारिक लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। यह चुनाव इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। समाज एक होने लगा, तो बांट कर राजनीति करने वालों का धरातल खिसकने लगा। इसलिए सब बांटने वालों ने इकटठें आ कर एक दूसरे का साथ देकर इस जोड़ने वाले, सर्वसमावेशक भारत का समर्थन कर सभी के विकास के सूत्र को विजयी बनाया है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आश्वासक और आनंद का यह दिन है। भारत की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। इस वैचारिक लड़ाई में भारत के पा के मजबूत नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

— **सम्पादक**

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा-
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com